Sl. No	Name o£ the State	Name of the Scheme				Total
		Freshwater Aquaculture	Brackish-water Aquaculture Fish culture project	Work Bank Assisted shrimp &	Fisheries Training and Extension	
		No. Location	No. Location	No. Location	No. Location	
17.	Punjab	1 Sangrur	1 Karangadu	—	2 Nathana ferozepur	3
18.	Rajasthan	1 Guwardi				1
19.	Tamil Nadu	1 Madras				2
20.	Tripura	1 Udaipur	1 Nazat	1 Digha	1 Lembucherra	2
21.	Uttar Pradesh	1 Jaunpur			1 Kulia	1
22.	West Bengal	1 S-24 Par-ganas				4
	TOTAL:	19	8	2	15	44

"कपार्ट" द्वारा काली-सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठन

*71. **श्री रामदेव भंडारी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 30 नवम्बर, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 493 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक अभियान तथा ग्रामीण, प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कपार्ट) द्वारा काली-सूची में दर्ज 359 स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन जिलों तथा राज्यों में है,

(ख) क्या उपर्युक्त संगठनों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठनों के नाम भी काली-सूची में दर्ज किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो उनके नाम, जिले और राज्य का ब्यौरा क्या है, और

(घ) काली-सूची में दर्ज किए गए स्वयंसेवी संगठनों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई का अद्यतन ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृति मंत्री (डा0 जगन्नाथ मिश्र) : (क) से (ग) 31.12.1995, तक, कापार्ट ने 224 स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में दर्ज किया है। इन स्वयंसेवी संगठनों की सूची अनुपत्र में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 176 (अनुपत्र संख्या 24) इसेक अतिरिक्त कापार्ट ने उन 152 स्वयंसेवी संगठनों को भी काली सूची में दर्ज किया है जिन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों ने काली सूची में दर्ज किया था। इन 152 स्यवंसेवी संगठनों को सूची अनुपत्र में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 176 अनुपत्र संख्या 25)

(घ) कापार्ट द्वारा की गई / की जाने वाली कार्रवाई में दोषी स्वयंसेवी संगठनों से धनराशियों की वसूली करना, काननी कार्यवाही शुरू करना, मामलों को पुलिस के पास भेजना, आदि शामिल है।

Effective implementation of Rural Drinking Water Supply Programme

*72 SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Central Government issued directions to the State Governments to set up institutional arrangements at State and district levels for the effective implementation of rural drinking water supply programmes;

(b.) if so, the financial assistance provided by the Central Government to the State Government of U.P. during the last one year for implementation of the programme;

(c) whether any guidelines in this regard have also been issued', arid

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (DR. JAGANNATH MISHRA): <a) The State Govemments have been advised to set up institutional arrangements in this behalf.

(b) Financiai assistance is not contemplated for setting up the mechanism as it is a part of normal administrative work.

(c) Yes, Sir.

(d) The details are given in the following statement.

Statement

Guidelines for the Constitution of Committees at the State / District level for implementing Rural Drinking Water Programme in accordance with policy / directions of Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission Authority.

High Level Committee:

Composition

Chief Minister /Lt. Governor —Chairman

Minister incharge of RWS, Rural Sanitation, Finance, Health, Education, Irrigation, Water Resources, .Science & Technology, —Members

Ground Water Development / Remote Sensing and Planning.

Functions

(i) To lay down policy regarding rural drinking water supply and sanitation under the State Minimum Needs Programme and other related programmes in line with the national policy.

(ii) Mobilise resources as per the funding pattern of the Central Government for assistance to the States.

(iii) Prioritise the work relating to the Rural Water Supply and Rural Sanitation.

(iv) Review the progress of the implementation. of the programmes.

(iv) Give appropriate directions in ,_— ^ interest of cost effective and accelerated implementation.

Empowered Committee

Composition

There is need for an Empowered Committee at the State level so that all decision related to rural drinking water supply and sanitation can be taken expeditiously. The Empowered Committee may be headed by the Chief Secretary as its Chairman and Secretary in-charge of RWS, Chief Engineer (PHED), Secretary (Finance), Secretary Planning, Secretary (Water Resources), Secretary (Health), Secretary (Education), Secretary (Irrigation), Secretary, (Science & Technology) and representatives of the State Ground Water Board, Remote Sensing Agencies and Central Ground Water Board at its members.

Functions

(i) To facilitate increase of resources and services of related Departments and Agencies.

(ii) To monitor and review the implementation of the projects/ schemes.

(iii) To sanction and approve projects/schemes under MNP, ARWSP and sub-missions.

(iv) To approve Annual Plans.

(v) To ensure coordination with various department for all the scientific inputs for ensuring sustainable water supply and sanitation systems.

(vi) To give appropriate directions to the implementing departments/ agencies in the State for efficient functioning of the Rural Water Supply and Sanitation activities.

District level Committee

Composition

District level Committees may be constituted with Chairperson of the Zilla Parishad/ Collector /CEO as the Chairpersons and representatives of the concerned Departments / Agencies may be included as members for effective coordination.

Functions

(i) To monitor and review the progress of works in the Districts.

(ii) To provide feed back to the State level Committee on various aspects of programme and problems encountered for possible policy changes/ solutions at the State level.

(iii) To prepare District Action Plans in consultation with Panchayats.

(iv) To assess / identify allocate resources under various schemes.

उर्वरकों की खपत

*73. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

श्री अनन्तराम जासवाल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिमा, पोटाश और फास्फेट की वार्षिक खपत कितनी-कितनी है और वर्ष 1991-92, 1993-94 और 1994-95 के दौरान नाइट्रोजन-फास्फेट-पोटाश की खपत का अनुपात कितना-कितना था,

(ख) वर्ष 1994 के दौरान यूरिया के दामों में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के उद्देश्य क्या थे और क्या ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या उर्वरक उद्योग ने उर्वरकों के उत्पादन में असंतुलन समाप्त करने के लिए कोई सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंण में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है, और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश की वार्षिक खपत तथा उर्वरक पोषक खपत अनुपात निम्नानुसार हैं:-

(लाख टनों में)

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
यूरिया	140.04	149.06	158.10	171.12
एन	80.46	84.27	87.89	95.07
पी	33.21	28.44	26.69	29.32
के	13.61	8.84	9.08	11.25
एन+पी+के	127.28	121.55	123.66	135.64
एनपीके अनुपात :	5.9:2,4:1	9.5:3,2:1	9.7:2,9:1	8.4:2,6:1

(ख) से (ग) यूरिया के मूल्य में बढ़ोत्तरी का उद्देश्य 25.8.1992 से उनके अनियंत्रण के कारण यूरिया के मूल्य में कमी तथा पी और के उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि द्वारा हुई एन पी के अनुपात में गड़बड़ी को ठीक करना था। एन पी के खपत अनुपात में 1993-94 में 9.7:2,9:1 से सुधार होकर 1994-95 में 8.4:2,6:1 हो गया है।

(घ) और (ड़) उर्वरक उद्योग ने उर्वरकों के उत्पादन में असतुंलन को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनियंत्रित उर्वरकों पर रियायत की राशि में वृद्धि तथा तदर्थ रियायत के दावों को तेजी से रिलीज करना शामिल है। जबकि दावों की तत्परता से जांच की जा रही है। बजटीय बाधाओं के कारण रियायत की राशि को बढ़ाना संभव नहीं हुआ है।